पुस्तक समीक्षा

भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा
7(1) 205–206, 2020
© 2020 Indian Sociological Society
Reprints and permissions:
in.sagepub.com/journals-permissions-india
DOI: 10.1177/2349139620921995
http://bss.sagepub.in

ग़ज़ाला शहाबुद्दीन और के. शिवरामकृष्णन (सं.), 2019, *नेचर कंज़र्वेशन इन द न्यू इकॉनमी: पीपुल, वाइल्डलाइफ ऐंड द लॉ इन इंडिया*, हैदराबाद: ओरिएंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, पृष्ठ xvi + 291, मूल्य: ₹895, आई.एस.बी.एन. 978-93-5287-613-6.

21वीं सदी के दौरान आर्थिक सुधारों तथा प्राकृतिक संसाधनों व खनिजों की माँग में वृद्धि हुई है इससे पर्यावरण, प्राथमिक संसाधनों, जैव विविधता तथा जंगलों पर अभूतपूर्व दबाव आया है। विकास ने विभिन्न संरक्षित पारिस्थितिक क्षेत्रों में प्रजातियों और निवास स्थानों के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया है। संरक्षण के लिए बने कानूनों, नीतियों तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के बढ़ते प्रयासों के बावजूद यह सब हो रहा है। इस संदर्भ में यह पुस्तक आर्थिक उदारीकरण के संरक्षण के प्रयासों तथा भारत में संरक्षण लक्ष्यों को पूरा करने के रास्ते में संस्थागत कानूनी, वैज्ञानिक, राजनीतिक तथा सामाजिक बाधाओं का नई अर्थव्यवस्था में प्रकृति संरक्षण के अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करती है।

समीक्षाधीन प्रस्तुत पुस्तक की शुरुआत ग़ज़ाला शहाबुद्दीन द्वारा पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के *सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडी* (सीएसआई) में 2015 के अंत में बिताए गए 2 महीनों के दौरान उस समय हुई जब उन्होंने भारत में वन्यजीव प्रबंधन की राजनीति का अध्ययन करने के लिए अनौपचारिक चर्चा की। तत्पश्चात सी.ए.एस.आई. के समर्थन से भारत में नई दिल्ली स्थित 'इंडिया हैबिटेट सेंटर' में 4–5 नवंबर 2016 को 'भारत में वन्य जीव संरक्षण: नीति से व्यवहार तक' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रस्तुत शोध पत्रों में पर्यावरण संबंधी नीति की दिशा में हाल ही में उठाए गए ऐतिहासिक कदमों पर प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में प्रस्तुत किए गए शोध पत्र पुस्तक का हिस्सा बन गए जिसमें मुख्य रूप से अंबिका अय्यादुरई, विकास, ग़ज़ाला शहाबुद्दीन, मेघना अग्रवाल, रूथ, बाई झाला क्यो कुरेशी, नेहा सिन्हा, कांची कोहली, मंजू मैनन, रिंकी सरकार, राजकमल गोस्वामी, गणेश, अर्चना वाली तथा कार्तिक शंकर के अतिरिक्त के. शिवरामकृष्णन की भूमिका शामिल है।

प्रथम अध्याय में अंबिका अय्यादुरई द्वारा अरुणाचल प्रदेश के मिशमी लोगों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सुविधा की कमी के लिए जिम्मेदार जटिल सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों का पता लगाने का प्रयास किया गया है। दूसरे अध्याय में बहुत बड़े ग्रामीण तथा उसके साथ लगते क्षेत्रों जिनमें कृषि भूमि, चारागाह तथा गहनता से उपभोग किए गए जंगलों की संरक्षण नीति की कमियों को उजागर किया गया। तीसरे अध्याय में भारत में प्रतिष्ठित बड़ी बिल्ली की प्रजातियों में से एक, चीते की प्रजनन योजना संबंधी नीतियों तथा प्रक्रियाओं का पता लगाया गया। पाँचवें अध्याय में आर्द्रभूमि नीति को स्पष्ट किया गया है। छठे अध्याय में कांची कोहली तथा मंजू तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा

चलाए जाने वाले विनियमन कार्यक्रम के माध्यम से तटीय विनियमन के इतिहास का पता लगाने की कोशिश करते हैं। अध्याय सात रिंकी सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में गाँव की समितियों के उदाहरण की सहायता से सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों को जानने की कोशिश की गई है। अध्याय आठ में आम भारतीय राजनीतिक चेतना से बहुत आगे वैश्विक जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र के दूरस्थ परिदृश्य को जानने का प्रयास किया गया है। नौवें अध्याय में भारत के पश्चिमी घाटों पर तथा विधानों के प्रभाव को रेखांकित किया गया है।

पूरे भारत में की गई केस स्टडीज़ के आधार पर इस पुस्तक के अध्यायों में आरक्षण नीतियों की विभिन्न संदर्भों में जाँच की गई है। इनमें उत्तर पूर्व भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, दिल्ली के जंगलों का प्रबंधन, पश्चिम हिमालय के चिलगोजा पाइन जंगलों एवं मेघालय के जयंतिया पहाड़ों के वर्षा वनों के संरक्षण तथा पश्चिम घाट में वन संरक्षण प्रमुख है। *नेचर कंज़र्वेशन इन द न्यू इकॉनमी* के अंतर्गत भारत में विभिन्न प्रजातियों के प्रजनन, तटीय संरक्षण तथा आर्द्रभूमि भूमि के प्रबंधन संबंधी कानूनों तथा विनियमन नीतियों पर अन्वेषण किया गया।

पुस्तक में विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि प्राकृतिक संसाधनों तथा आवासों के दबाव बढ़ने के साथ ही आर्थिक उदारीकरण से संरक्षण के प्रयासों में भी वृद्धि हुई है। अंततः प्रकृति का प्रबंधन, संगणना, विनियमन और व्यावसायीकरण के अधीन कर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में लेखकों ने वन्य जीवन, स्थानीय लोगों, संस्थाओं तथा सामाजिक परिवर्तन के बीच संबंधों तथा संरक्षण में विज्ञान की भूमिका का अध्ययन किया है।

यह पुस्तक दृढ़तापूर्वक इस तथ्य को प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार आर्थिक उदारीकरण से संरक्षण एवं आवास कानूनों, जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण संबंधी कानूनों तथा संरक्षण के नए दृष्टिकोण के प्रति दबाव बढ़ा है। फलस्वरूप सामुदायिक संरक्षण तथा सामाजिक एवं निजी उद्यम के माध्यम से अमूल्य परितंत्र संबंधी सेवाओं के संरक्षण की दोबारा जाँच की गई।

अभी भी ऐसी कम ही पुस्तकें हैं जिनमें प्रकृति तथा वन्य जीव संरक्षण के लिए जैविक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान/मानविकी के विभाजन समाप्त करने का प्रयास किया गया है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भी इस पुस्तक का विशेष स्थान है। यह पुस्तक पर्यावरण अध्ययन संरक्षण, जीव विज्ञान, मानवविज्ञान, समाजशास्त्र तथा दक्षिण एशियाई अध्ययन के विद्वानों के लिए एक मूल्यवान कृति है। नीति प्रबुद्ध मंडलों (थिंक टैंक), सरकारी विभागों तथा गैर-सरकारी संगठनों के लिए भी यह पुस्तक उपयोगी है।

सुजीत सरोच
सह-आचार्य, समाजशास्त्र
एस.सी.वी.बी. गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, पालमपुर -176061
हिमाचल प्रदेश
ई-मेल: sujitsurroch@gmail.com